THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Government is in the process of formulating a New Education Policy for which it carried out a highly participative, inclusive and multi-pronged consultation process, through online, grassroots and thematic expert consultations. The Committee for the Draft National Education Policy under the Chairmanship of Dr. K. Kasturirangan submitted its report to the Ministry on 31st May 2019. The Draft NEP 2019 which was uploaded on the Ministry's website and also at *innovate.mygov.in* platform has received a large number of suggestions/comments from all stakeholders including Government of India Ministries and State Governments. Currently, the Ministry is in the process of finalising the National Education Policy, 2019 based on the Draft NEP report submitted by the Committee to Draft NEP, and the stakeholder feedback thereon.

(d) The requirement of funds would be estimated after finalisation of the Policy. Government is committed to implement the Policy by making suitable budgetary allocations.

Financial expenditure of educational reforms

*259. SHRI RAJMANI PATEL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to bring educational reforms in the country;

(b) whether these reforms would involve financial expenditure; and

(c) if so, the details of financial expenditure involved?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Government is in the process of formulating a New Education Policy for meeting the changing dynamics of the population's requirement with regard

to quality education, innovation and research, aiming to make India a knowledge superpower. In this regard, the Committee for the Draft National Education Policy under the Chairmanship of Dr. K. Kasturirangan submitted its report on 31st May 2019. The requirement of funds would be estimated after finalisation of the Policy. Government is committed to implement the Policy by making suitable budgetary allocations.

DR. SASMIT PATRA: Sir, my first question to the hon. Minister is: Would the hon. Minister provide details of the consultation process with reference to the National Education Policy, 2019 in so far as how many consultations were held, where they were held, what the scope of the consultations were and what have been the possible outcomes of the consultations?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह 33 वर्षों के बाद आने वाली नयी शिक्षा नीति के जिस मसौदे पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ कि यह दुनिया का सबसे बड़ा खुला नवाचार था, जब अक्टूबर, 2015 से यह प्रक्रिया शुरू की गयी। श्रीमन्, यदि मैं तिथिवार देखूँ, तो बहुत लम्बा हो जायेगा, लेकिन 14.02.15 से लेकर 21.03.2015 को सारे देश के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से, शिक्षा सचिवों से बातचीत होने के बाद आज टी.एस.आर. सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है, फिर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट पर राज्य सभा में चर्चा होती है, लोक सभा में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद जितने सुझाव आते हैं, उसके बाद फिर कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में एक नयी कमेटी गठित होती है। श्रीमन्?, इस बीच यदि देखें, तो लगभग जमीनी स्तर पर जो परामर्श हुआ है, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों .. लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 6000 शहरी स्थानीय निकाय, 676 जिलों और 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापक समयबद्ध भागीदारी को परामर्श किया है। मैं समझता हूं कि लगभग दो लाख और सुझाव व्यापक मशवरे के साथ आए हैं।

DR. SASMIT PATRA: Sir, my second supplementary. India is the land of Takshashila and Nalanda. Would the hon. Minister like to clarify the scope and focus of the National Education Policy in so far as bringing in the heritage, culture and ethos of India to the education curriculum and academic ecosystem?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, बहुत अच्छी चिंता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है। क्योंकि इस देश को विश्व गुरु कहा गया है -

'एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः ।
स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।।

तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, जहां पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। कुछ तो बात थी कि यह देश दुनिया में विश्व गुरु था। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वह भारत केन्द्रित होगी। वह भारत के ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान से युक्त होगी, वह संस्कारयुक्त होगी, अनुभव पर आधारित होगी, परिणाम आधारित होगी, भारत केन्द्रित होगी, अनुसंधानयुक्त अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को भी रखेगी, मूल्यपरक होगी, उद्यमिता से युक्त होगी, कौशलयुक्त होगी, रोजगारपरक होगी, प्रतिस्पर्धात्मक होगी, सशक्त अभिव्यक्ति के गुण भी होंगे, नवाचार होगा, अनुसंधान होगा और प्रौद्योगिकी भी होगी। यह जो नई शिक्षा नीति आ रही है, यह दुनिया में भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

श्री राजमणि पटेल: माननीय उपसभाध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। माननीय सदस्य की जो चिंता है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि वर्तमान समय में 'परामर्श' हो, चाहे 'दीक्षारंभ' हो, 'लीप' हो या 'निष्ठा' हो - NISHTHA - 42 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। श्रीमन्, चाहे NIRF - जो रैंकिग हम लोगों ने शुरू की है, National Digital Library हम लोगों ने शुरू की है। इसी तरह से HEFA है, जिसमें अवस्थापना के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए अलग से HEFA के तहत दिए जाएंगे। इसी तरह से IMPRESS है, IMPRINT है, SPARC है, GIAN है, PMMMNMMT है, PMFR है, अनुसंधान के क्षेत्र में है, ध्रुव कार्यक्रम है, Study in India कार्यक्रम है, Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements है । श्रीमन्, नयी योजनाएं, जो शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, ऐसे दर्जनों कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनका रिज़ल्ट भी मिल रहा है।

श्री राजमणि पटेल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अमीर और गरीब को एक समान शिक्षा मिल सके, क्या नयी शिक्षा नीति में इसका भी कोई प्रावधान है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, हमारी सरकार ने आज भी गरीब और अमीर की खाई को पाटा है। समग्र शिक्षा के तहत, सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सब बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त हो सके, उसे हम इस नयी शिक्षा नीति में भी लेकर आ रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य की चिंता है कि जो गरीब है, उसका बच्चा किसी तरह से पढ़ पाए तो हम लोगों ने सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम में न केवल सरकारी स्कूलों में, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें भी 25 प्रतिशत का आरक्षण रखा है। जो

प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्हें भी अनिवार्य रूप से उन गरीब बच्चों को लेना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि उसमें इस समय 44 लाख छात्रों का, प्राइवेट स्कूलों में नामांकन हुआ और उसके ऊपर हम 1,100 करोड़ की धनराशि हम उन पर व्यय कर रहे हैं।

PROF. M. V. RAJEEV GOWDA: Sir, the focus on Foundational Literacy and Numeracy in the draft NEP is good, but the policy does not define it in measurable terms. For example, a child in grade II must be able to read 40 words per minute. Will this programme, Foundational Literacy and Numeracy, be defined in measurable terms and what are your plans to monitor these outcomes?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : श्रीमन्, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वह निश्चित रूप से इन सबसे युक्त होगी, इसलिए हमने कहा है कि जो तीन वर्ष का बच्चा है, पढ़ने के बाद उसमें अंदर से जिज्ञासा होती है, प्रतिभा होती है, जो वह प्राप्त करता है। जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वह निरंतर मूल्यांकन भी करेगी और माननीय सदस्य की जो यह चिंता है कि उसका जो पाठ्यक्रम होगा, उसको वह ग्रहण कर भी पा रहा है या नही और यदि ग्रहण नही कर पा रहा है, तो वैकल्पिक रूप में उसको कैसे उठाया जाएगा, यह नई शिक्षा नीति का पार्ट है, जो सबके सामने है।

DR. SANTANU SEN: Sir, I am really happy to have you on the Chair.

My supplementary question to the hon. Minister is on the National Education Policy. As it is known to all by now that several objections have been received from various stakeholders on the NEP, so my supplementary to the hon. Minister is: What is the blueprint of the Government of India to address these legal, legitimate and valid expectations of several stakeholders?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, जो मोटा-मोटा है, वह मैंने अभी बताया कि हमारी नई शिक्षा नीति किस रास्ते से होकर गुजरेगी। लेकिन जहाँ तक माननीय सदस्य की आशंका है, उसके संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह तो पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। इस पर बड़े पैमाने पर परामर्श होने के बाद, राज्य सभा और लोक सभा में चर्चा होने के बाद, लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों, विधायकों, शिक्षा मंत्रियों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, छात्रों और अभिभावकों से परामर्श करने के बाद भी उसको पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। अगर अभी भी किन्ही के पास कोई ऐसे सुझाव होंगे, तो वे देंगे और उन्ही सुझावों के आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है।

श्री राकेश सिन्हा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि बड़े लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा नीति को तैयार करने की कोशिश हो रही है। इस पर

व्यापक परामर्श हुआ है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है और वह यह है कि जिस प्रकार से निजी विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और हम अपने जो राज्य केंद्रित विश्वविद्यालय हैं, उनमें छात्रों को प्रवेश नही दे पा रहे हैं और छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस स्थिति में निजी विश्वविद्यालय के प्रति इस शिक्षा नीति में क्या नीति अपनाई जा रही है, जिससे एक समतुल्य बना रहे? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि निजी विश्वविद्यालयों में जो फी का स्ट्रकचर है और सिलेबस है, क्या दोनों पर सरकार का नियंत्रण हो पाएगा या नही?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, इस समय इस देश के अंदर एक हजार से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45 हजार से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं। हम लोगों ने यह कोशिश की है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो परामर्श कार्यक्रम रखा है, उसके अंतर्गत रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऊपर आता है, उसके इर्द-गिर्द जो पाँच महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होंगे, वह उनका मार्गदर्शक बनेगा और उनको उस रैंकिंग पर लाने के लिए जो-जो भी व्यवस्थाएं उनको चाहिए, वे सभी उनको हम देंगे। इस कारण से अभी तक 800 महाविद्यालयों को स्वायत्तता दी गई है और इस सरकार की यह मंशा है कि संस्थाओं को स्वायत्तता दी जाए ताकि वे आगे बढ़ सकें।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, कोई भी नीति तब तक कोई बड़ा सुधार नही कर सकती है, जब तक कि शिक्षा के क्षेत्र में योग्य गुरुओं की तलाश नही होगी और जब तक तक योग्य गुरु नही मिलेंगे। जिस तरह से दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही जो ज्ञानी गुरु होता है, वह विद्यार्थी के अज्ञान को दूर करता है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस क्वालिटी के टीचर्स उपलब्ध नही हैं। क्या माननीय मंत्री जी कोई इस तरह का मापदंड निर्धारित करेंगे, जिससे बेहतर किस्म के टीचर्स उपलब्ध हो सकें, क्योंकि जब तक अध्यापक सही किस्म का नही होगा, तब तक आप यह शिक्षा नीति या कोई भी नीति लाइए, वह कारगर हो ही नही सकती है।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, प्रोफेसर साहब स्वयं ही शिक्षक हैं और बहुत ही योग्य शिक्षक हैं। श्रीमन्, मैं उनको और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अच्छे अध्यापक कैसे रहें, निष्ठा, जिसकी चर्चा की, और उच्च शिक्षा में अर्पित, जो बाकायदा हर वर्ष ट्रेनिंग करेगा और देगा तथा यदि वे उस आधार पर नही आते हैं, तो उनको पदोन्नति नही दी जाएगी, यह already शुरू कर दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Question No. 260.

Implementation of Shaala Darpan Initiative in KVs

*260. SHRI SANJAY SETH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state: